**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2995**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**विदेशी तेल कम्पनियों को अन्वेषी ब्लॉकों की पेशकश**

**2995. श्री भुवनेश्वर कालिताः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विदेशी कम्पनियों को तेल और गैस ब्लॉकों के अन्वेषण की पेशकश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तेल और गैस क्षेत्र में सरकार को प्राप्त प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कुछ बड़ी वैश्विक तेल कम्पनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, यदि हां, तो इस प्रकार की कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितना निवेश किया गया है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (घ):** भारत सरकार ने दिनांक 10.03.2016 को हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण लाइसेंसिंग नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नई अन्‍वेषण लाइसेंसिंग नीति में पारंपरिक और साथ ही गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों के अन्‍वेषण और दोहन के लिए एक ही लाइसेंस की व्‍यवस्‍था है। खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तौर-तरीके लागू करके रूचि की अभिव्‍यक्ति (ईओआईज़) आमंत्रित करने का पहला दौर  01 जुलाई, 2017 से 15 नवंबर, 2017 तक खुला था। प्राप्‍त हुई रूचि की अभिव्‍यक्तियों के आधार पर 55 ब्‍लॉक तैयार किए गए हैं और इनके लिए अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से दिनांक 19 जनवरी, 2018 से बोली के लिए रखा गया है।

\*\*\*\*\*